the event of death, the amount of insurance as indicated above plus the savings element together with interest thereon is payable to the eligible heirs. On retirement, the personnel receive the total savings to their credit (based on their length of service and actual contribution towards the scheme) and interest thereupon. Thus the scheme helps the family in the event of death of personnel in service; and towards resettlement of person-on retirement.

मध्य प्रदेश जनजाति सहकारी विकास निगम

3793. श्री भागीरथ भंवर : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मध्य प्रदेश जनजाति सहकारी विकास निगम के जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा करोड़ों रूपये दिये गये हैं, घाटे और घोटाले के बारे मे नियुक्त जांच आयोग का प्रतिवेदन इस बीच प्राप्त हो गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

(ख) केन्द्रीय सरकार ने ऋणों और अनुदानों के रूप मे अब तक निगम को कितनी धन राशि दी है ; और

(ग) इस समय इसका कार्य कैसा चल रहा है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) मध्य प्रदेश जनजाति सहकारी विकास निगम के कार्यकरण की जांच करने के लिए कोई औपचारिक जांच आयोग नियुक्त नही किया गया है। फिर भी राज्य सरकार द्वारा एक प्रशासनिक जांच की गई थी जिस में निगम के कार्यकर मे दीर्घ कालिक सुधारों के संबंध मे कुछ सुझाव दिये गये हैं।

(ख) जनजाति सहकारी विकास संघ को ऋण तथा सहायक अनुदान के रूप में केन्द्र द्वारा दी गई कुल धन राशि 214.65 लाख रुपये है ।

(ग) मध्य प्रदेश जनजाति सहकारी विकास संघ में निगम का पुनर्गठन किया गया है । राज्य सरकार ने सूचित किया है कि इस समय संघ काफी संतोषजनक ढंग से कार्य कर रहा है ।

Report of National Sample Survey regarding persons living below Poverty Level

3794. SHRI SAMAR GUHA: Will the Mimser of PLANNING be pleased to state:

(a) whether Government have received the report of National Sample Survey regarding percentage of persons living below poverty level in different States;

(b) if so, facts thereabout,

(c) whether the findings of the National Sample Survey tally with the earlier findings of the Planning Committee,

(d) if not, facts thereabout, and

(e) whether these figures about the persons living below poverty level are proposed to be considered by the Planning Committee in regard to formulating its policies?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING (SHRI SANKAR GHOSE): (a) No. Sir. The National Sample Survey have not prepared such a report

(b) to (d). In view of (a) the quesetion does not arise.

(e) In view of (a) above the question does not arise. However, the

reports of the National Sample Survey on consumer expenditure and other subjects are continually analysed in the Planning Commission.

ट्रैक्टरों की सप्लाई के लिए टर्की के साथ करार

3795. **श्री हुकम चन्द कछवाय :** क्या उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषकों को ट्रैक्टर प्राप्त करने के लिये काफी समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है और उन्हें ट्रैक्टर बाजार में निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर खरीदने पड़ते हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) देश में आपात स्थिति की घोषणा के बाद कितने ट्रैक्टर आयात किये गए ;

(घ) क्या हजारों ट्रैक्टरों की सप्लाई के लिये भारत ने अप्रैल, 1976 में टर्की के साथ करार किया है ; और

(ङ) यदि हां, तो किस मूल्य पर और इसे भारत में किस मूल्य पर बेचा जा रहा है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) :

(क) और (ख). दो माडलों के ट्रैक्टरों को छोड़कर देश में बन रहे सभी ट्रैक्टर बिना किसी प्रतीक्षा के उपलब्ध हैं। ग्राहकों से निर्धारित मूल्यों में अधिक वसूल किये जाने के बारे में सरकार को पता नहीं है ।

(ग) आपात स्थिति की घोषणा किये जाने के पश्चात् ट्रैक्टरों का कोई आयात नहीं किया गया है। विश्व बैंक द्वारा दिए गए धन से आई० डी० ए० कृषि परियोजना के अधीन 1100 ट्रैक्टर आयात किये गये थे ।

(घ) और (ङ). ट्रैक्टर निर्माण कर रहे एक एकक ने प्रति ट्रैक्टर 38,000 रुपये के अनुमानित मूल्य से 1000 ट्रैक्टरों की सप्लाई करने के लिए फरवरी, 1976 में टर्की से एक करार किया है जब कि इन ट्रैक्टरों का मूल्य देश में उत्पादन शुल्क समेत 48,550 रुपये है ।

विदेशी मुद्रा (विनियमन) अधिनियम के बारे में शीतल पेय आदि निर्माताओं से अभ्यावेदन

3796. **श्री सोमचन्द सोलंकी :** क्या उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शीतल पेय आदि निर्माती कम्पनियों ने विदेशी मुद्रा (विनियमन) अधिनियम के संबंध में कोई ज्ञापन सरकार को भेजा है ;

(ख) यदि हां, तो उन कम्पनियों के क्या नाम हैं ; और

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) :

(क) और (ख). जुलाई, 1975 में कोका कोला बाटलर्स एसोसियेशन आफ इण्डिया ने विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 के उपबन्धों के अन्तर्गत कोका कोला एक्सपोर्ट कारपोरेशन की भावी रूप-रेखा बताते हुए एक अनन्तिम प्रस्ताव भेजा था।